पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

सिविल रिट 1984 का मामला सं. 4915

इस पर निर्णय लिया गया: 03.01.1987

याचिकाकर्तागण: प्रवीण शंकर सिंह और अन्य।

बनाम

उत्तरदातागण: बिहार राज्य और अन्य।

खंडपीठ द्वारा पूर्ण पीठ को निर्देश(रिफरेन्स) जो बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 की धारा 45बी की व्याख्या से संबंधित है जिसमें *यमुना राय बनाम बिहार सरकार (मनु/बी.एच./0058/1984)* में दी गयी व्याख्या पर संदेह व्यक्त किया गया।

एस.एस. संधवालिया, मुख्या न्यायाधीश ने यह कहते हुये निर्देश को निपटा दिया कि दोनों ही पक्षों के वकील यमुना राय में 45-बी की व्याख्या से सहमत है। जबकि बी.पी.सा., न्यायाधीश एक.एम.शर्मा न्यायाधीश के मत से सहमत रहे।

एल.एम.शर्मा, न्यायाधीश ने निर्णित किया कि यमुना राय में धारा 45-बी व्याख्या पूरी तरह से सही है। उनके अनुसार नये सामग्री के प्रकट होने पर राज्य सरकार या जिला समाहर्ता फिर से निपटाये गये मामलों को खोल सकती है। फिर निर्णित किया गया कि मामलें खोलने पर पक्षकारों को सूचित किया जाना चाहिये।

[पारा 16 और 17]

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

सिविल रिट 1984 का मामला सं. 4915

इस पर निर्णय लिया गया: 03.01.1987

याचिकाकर्तागण: प्रवीण शंकर सिंह और अन्य।

बनाम

उत्तरदातागण: बिहार राज्य और अन्य।

माननीय न्यायाधीश/कोरम:

एस. एस. संधवालिया, मु. न्या., बी. पी. झा और एल. एम. शर्मा, न्यायमूर्तिगण

अधिवक्ता:-

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिए: बिनोद कृष्ण झा, सुभाष चंद्र झा, प्रमोद कुमार सिंह और ज्योत्सना ठाकुर, अधिवक्तागण

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिए: जे. एन. पी. सिन्हा, सरकारी अधिवक्ता, अंजनी कुमार सिन्हा और सुबोध प्रसाद सरकार के कनिष्ठ अधिवक्ता और रतन कुमार सिंह और जुगल किशोर, अधिवक्ता (नंबर 5 के लिए)।

निर्णय

एस. एस. संधवालिया, मुख्य न्यायाधीश

1. पूर्ण पीठ के इस संदर्भ में अब तथ्यों को फिर से बताना पूरी तरह से अनावश्यक है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ विवाद बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 की धारा 45बी में उपयोग की गई भाषा पर आधारित है जो निम्नलिखित शब्दों में है:--

“राज्य सरकार या जिले का समाहर्ता, जो इस ओर से अधिकृत हो सकता है, किसी भी समय अधिनियम के तहत समाहर्ता द्वारा निपटाई गई किसी भी कार्यवाही के किसी भी अभिलेख की मांग और जांच कर सकता है और यदि वह उचित समझता है, तो निर्देश दे सकता है कि मामले को फिर से खोला जाए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से निपटाया जाए। ”

यह अच्छी तरह से स्मरण होना चाहिए कि स्वीकार करने के बहुत ही अंतिम चरण में, धारा 45 बी के तहत विवादित आदेश को चुनौती देने में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया था कि रिकॉर्ड पर किसी भी नई सामग्री या नई जानकारी के अभाव में मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है। इस विवाद के लिए बुनियादी निर्भरता यमुना राय बनाम बिहार राज्य मनु/बी. एच./0058/1984 मामले में खंड पीठ के फैसले पर थी। हालाँकि, प्रस्ताव पीठ ने यमुना राय के मामले में दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में संदेह व्यक्त किया। इस मुद्दे के महत्व और अधिकतम सीमा वाले कानूनों के तहत मामलों में इसकी आवृत्ति को देखते हुए, उन्होंने निम्नानुसार टिप्पणी किया:-

“हम, तदनुसार, यमुना राय और अन्य (ऊपर) के मामले में निर्धारित कानून की शुद्धता पर विचार करने के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजते हैं। ”

2. जैसा कि पहले स्वीकार करने वाली पीठ ने हमारे सामने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा यमुना राय बनाम बिहार राज्य पर उनके संदर्भ और निर्भरता को दोहराया। यह प्रस्तुत किया गया था कि बारीकी से जांच करने पर यह किसी भी तरह से न्यायालय के भीतर पहले की मिसाल की रेखा से विचलित नहीं हुआ। शिव शंकर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य मनु/बी.एच./0038/1982 का संदर्भ दिया गया था: 1982 बी. बी. सी. जे. (एच. सी.) 362, श्री ठाकुर राम जानकीजी बनाम बिहार राज्य 1983 बी. एल. जे. आर. 33 और हरिश्चंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य मनु/बी.एच./0098/1984: 1984 पीएलजेआर 988।

3. कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने यमुना राय के मामले मनु/बी.एच./0058/1984 में दृष्टिकोण की शुद्धता की चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किया। यहाँ जबकि स्पष्ट रूप से उनसे पूछा गया है। उन्होंने यह रुख अपनाया कि इसके विनिश्चय आधार को चुनौती देने के बजाय, उन्होंने उस पर भरोसा किया। विद्वान वकील के अनुसार, उक्त मामले में टिप्पणियाँ, समग्र रूप से पढ़ने पर पिछली निर्णित सारी फैसलों धारा के अनुरूप थीं।

4. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह कुछ हद तक स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ अब निष्फल हो गया है। यह स्पष्ट रूप से अनावश्यक है और, शायद, उस दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में राय देना अनुचित है जिसके बारे में पक्षों के विद्वान वकील स्वयं सहमत हैं और जिसके संबंध में अब हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं उठाई गई है।

5. मामला अब गुण-दोष पर निर्णय के लिए एक उपयुक्त पीठ के पास वापस जाएगा।

बी. पी. झा न्यायमूर्ति

6. मैं अपने भाई, माननीय न्यायमूर्ति एल. एम. शर्मा द्वारा प्रस्तावित और दर्ज किए गए आदेश से सहमत हूँ।

एल. एम. शर्मा न्यायमूर्ति

7. इस रिट आवेदन को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने यमुना राय बनाम बिहार राज्य, 1984 पैट एल. जे. आर. 480(ए. आई. आर. 1984 पटना 195) में निर्णय की शुद्धता पर गंभीरता से संदेह किया: और इसे पूर्ण पीठ को भेज दिया। निर्देश के क्रम में, पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:--

“बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 45-बी के तहत पारित विवादित आदेशों (अनुलग्नक 2 और 3) को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए बिंदुओं में से एक यह है कि रिकॉर्ड पर किसी भी नई सामग्री या नई

जानकारी के अभाव में, मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता था, इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने यमुना राय बनाम बिहार राज्य 1984 पटना एल. जे. आर. 480 मामले में इस अदालत के एक पीठ के फैसले पर भरोसा किया:

हम उपरोक्त मामले में खंड पीठ की टिप्पणियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ पाते हैं। हमारी राय में, अधिनियम की धारा 45-बी के तहत समाहर्ता को प्रदत्त शक्ति व्यापक है क्योंकि इस प्रावधान की भाषा उन्हें अधिनियम के तहत समाहर्ता द्वारा निपटाई गई किसी भी कार्यवाही के किसी भी रिकॉर्ड की मांग करने और जांच करने के लिए अधिकृत करती है, और फिर यदि वह संतुष्ट महसूस करते हैं, तो वह निर्देश दे सकते हैं कि मामले को फिर से खोला जा सकता है। ”

8. इस मामले की सुनवाई हमारे सामने 18-9-86 और 20-9-86 को हुई थी जब इस न्यायालय के कई खंड पीठ के फैसलों को हमारे सामने रखा गया था, और इस मामले पर बार में कुछ देर तक बहस हुई थी। चूंकि जिस पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा है, वह यमुना राय के मामले में निर्णय की शुद्धता के बारे में हमारी राय मांगती है और चूंकि हमने मामले को विस्तार से सुना है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे निर्दिष्ट प्रश्न पर अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। नीचे दिए गए कारणों से, मेरी राय में, यमुना राय के मामले का सही निर्णय लिया गया था और हमारे सामने विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा लिया गया रुख उचित और सही था। मुझे नहीं लगता कि चूंकि राज्य ने हमारे सामने उचित रवैया अपनाया है, इसलिए हमें इस प्रश्न पर मांगी गई अपनी राय को खंड पीठ को अस्वीकार कर देना चाहिए।

9. जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, यह प्रश्न बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 की धारा 45 बी की व्याख्या से संबंधित है। इस धारा ने किसी भी बंद कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए व्यापक अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारियों को निहित किया है और एकमात्र सीमा का उल्लेख किया

गया है कि "यदि वह उचित समझता है" तो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि सर्वनाम "यह" कलेक्टर के लिए उपयुक्त नहीं है, यह माना जाना चाहिए कि खंड "यदि वह उचित समझता है" राज्य सरकार और कलेक्टर दोनों पर लागू होता है; क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है कि विधायिका का उद्देश्य मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद ही राज्य को फिर से खोलने की शक्ति प्रदान करना था, और साथ ही कलेक्टर को बिना किसी कारण के, यानी मनमर्जी से कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था।

10. सवाल यह है कि खंड में "यदि यह उचित समझता है" अभिव्यक्ति के सम्मिलन का प्रभाव क्या है। इसका अर्थ है कि संबंधित प्राधिकारी को पर्याप्त कारण के बिना कार्य नहीं करना है। इसलिए कार्यवाही को केवल पिछले आदेश की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए अनावश्यक कारणों से पुनः विलोकन के नाम पर फिर से नहीं खोला जा सकता है। अगला सवाल उस प्रक्रिया के बारे में है जिसके द्वारा प्राधिकरण को यह तय करना है कि कोई विशेष कार्यवाही फिर से खोलने के लिए उपयुक्त है और ऐसा निर्णय लेने का आधार क्या है। यदि प्रश्न के लिए प्रासंगिक नई सामग्री की खोज की जाती है, जिसे यदि अभिलेख पर मौजूदा सामग्री के साथ माना जाता है, तो एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना है, तो कार्यवाही को निश्चित रूप से फिर से खोला जा सकता है। ऐसे मामले के बारे में जहां प्राधिकरण पहले से मौजूद सामग्री के आधार पर मामले की फिर से जांच करने का फैसला करता है? इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने से पहले, जिस पर खंड पीठ ने इस पीठ की राय मांगी है, मैं यमुना राय के मामले के विनिश्चय आधार पर चर्चा करना चाहूंगा।

11. उस मामले में, समाहर्ता ने भूमि-धारकों को 4 यूनिट भूमि दी थी जो एक हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य थे, और चूंकि राज्य सरकार की राय थी कि यह एक गलत आदेश था, इसलिए उसने भूमि-धारकों को नोटिस जारी किए बिना मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया। पीठ का गठन करने वाले दोनों विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि जो पक्ष प्रभावित होने वाले थे, वे मामले को फिर से खोलने से पहले नोटिस के हकदार थे। न्यायमूर्ति श्री बी. पी.

झा ने आगे धारा के दायरे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 45-बी के तहत कार्य करने से पहले संबंधित प्राधिकारी के पास नई सामग्री होनी चाहिए। संदर्भ के आदेश (एक बड़ी पीठ को वर्तमान रिट आवेदन के) की अवधि से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि किसी कार्यवाही को फिर से खोलने से पहले, यह आवश्यक था कि ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जो मामले के रिकॉर्ड में पहले नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि यमुना राय के मामले मनु/बी.एच./0058/1984 में फैसले की यह सही व्याख्या है। निर्णय के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित टिप्पणियों को देखा जा सकता है:

“इसलिए, मामले को फिर से खोलने के लिए, राज्य सरकार या जिला समाहर्ता के पास नई सामग्री होनी चाहिए जो निर्णय देने के समय उपलब्ध नहीं थी। यह सामग्री राज्य सरकार या जिला समाहर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर या अभिलेख से भी हो सकती है। मान लीजिए कि कुछ जानकारी आंचल अधिकारी या समाहर्ता के पास उपलब्ध हो सकती है, जिस पर समाहर्ता ने आदेश पारित करते समय अपना दिमाग नहीं लगाया, वह जानकारी जिस पर पहले के प्राधिकरण द्वारा दिमाग नहीं लगाया गया था, एक मामले को फिर से खोलने के लिए जानकारी या सामग्री का स्रोत हो सकती है। ”

इसलिए, यह स्पष्ट है कि श्री न्यायमूर्ति बी. पी. झा ने कुछ नई सामग्री की खोज को, जो अभिलेखों में नहीं थी, शक्ति के प्रयोग के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में नहीं रखा।

12. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि-धारक की अधिशेष भूमि निर्धारित करने के उद्देश्य से अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया विस्तृत है जिसमें अपील का अधिकार और पुनरीक्षण की शक्ति शामिल है। परिणामी परिणाम की प्रकृति को देखते हुए, कार्यवाही स्पष्ट रूप से न्यायिक सदृश प्रकृति की है। अचल संपत्तियों में निहित अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है और नए अधिकार बनाए जाते हैं। जब भूमि-धारक जो अपनी संपत्ति से वंचित हैं और लाभार्थी राज्य निर्धारित अधिकारियों द्वारा निर्णय की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मामलों पर भिन्न होते हैं,

तो एक कानून विवाद अस्तित्व में आता है। प्राधिकरण द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर गहन जांच के बाद, एक निर्णय लिया जाता है जिसका अपील और पुनरीक्षण शक्तियों के तहत परीक्षण किया जाता है। आम तौर पर, इस तरह के विस्तृत परीक्षण से गुजरने के बाद प्राप्त अंतिम परिणाम को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए। "पुनः प्रकाशन और अंतिम निर्णय के हित" के सिद्धांत, यानी, यह राज्य के लिए चिंता का विषय है कि कानूनी मुकदमों का अंत हो और "अपराध निवारण और सुधार", यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से आकर्षित होते हैं। यद्यपि उक्त सिद्धांत बहुत पहले निर्धारित किए गए थे, लेकिन उनका हमेशा सम्मान किया गया है। सर लॉरेस जेनकिंस ने शिओपरसन सिंह बनाम राम नंदन प्रसाद नारायण सिंह ए. आई. आर. 1916 पी. सी. 78 में कोक के हवाले से कहा कि बंद कार्यवाही में पारित आदेशों की अंतिमता से संबंधित नियम की अनदेखी करके, कानून के नाम पर महान उत्पीड़न किया जा सकता है, और फिर देखा कि यह सिद्धांत जो प्राचीन मिसाल पर स्थापित किया गया था, विवेक द्वारा निर्धारित किया जाता है जो हमेशा के लिए है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सिद्धांत रोमन न्यायशास्त्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्राचीन हिंदू कानून में इसे मान्यता दी गई थी, जैसा कि कात्यायन के पाठ से स्पष्ट है जो सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार करता है:

“यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से पराजित होने के बावजूद, फिर से मुकदमा करता है, तो उसे जवाब दिया जाना चाहिए कि 'आप पहले हार गए थे'। इसे पूर्व निर्णय का सिद्धांत कहा जाता है। ”

13. अधिनियम के मूल निर्माताओं ने इस असाधारण प्रावधान (धारा 45-बी के तहत) को शामिल नहीं किया था जिसे बाद में एक संशोधन द्वारा पेश किया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून में धारा 45-बी जोड़ते समय, विधायिका ने अधिकार के प्रयोग के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की थी। यह बार-बार कहा गया है कि परिसीमा का कानून धोखाधड़ी को दबाने और समय बीतने के बाद उत्पन्न होने वाले सबूतों की कमी को पूरा करने

की दृष्टि से विश्वास पर आधारित कानून हैं। वे इसे कुछ हद तक सही के बराबर बनाकर परिश्रम को तेज करते हैं। वे मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करते हैं। जॉन वोएट को स्टोरीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज में यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि यदि विवाद एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं हैं, तो वे अमर हो जाएंगे जबकि पुरुष नश्वर हैं। प्लंबर, एम. आर. ने चोलमॉन्डेले बनाम क्लिंटन, 2 जैक और डब्ल्यू. 140 में कहा कि जनता "समुदाय की शांति के लिए मुकदमेबाजी के लिए कानून द्वारा निर्धारित एक ज्ञात सीमा रखने में बहुत रुचि रखती है, और यह कि एक कतिपय निश्चित अवधि हो सकती है, जिसके बाद स्वामी को पता चल सकता है कि उसके शीर्षक और अधिकार प्रश्नगत नहीं उठाया जा सकता है। यह बेहतर है कि लापरवाह मालिक, जिसने एक निर्धारित अवधि के भीतर अपने अधिकार का दावा करने में चूक की है, अपना अधिकार खो दे, इससे कि पक्षकारों को पुरानी मांगों द्वारा परेशान किए जाने के लिए एक अंतहीन मुकदमेबाजी के लिए एक उद्घाटन दिया जाना चाहिए।

14. ये सिद्धांत हर सभ्य समाज और हर उम्र के लिए असाधारण हैं। धारा 45-बी की व्याख्या इसी पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए।

15. इसलिए, यह सुझाव देना व्यर्थ है कि राज्य और समाहर्ता को बंद कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए एक मनमाना शक्ति प्रदान की गई है, जब भी वे ऐसा करने के लिए इच्छुक हों। यह नहीं माना जा सकता है कि विधायिका गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही थी ताकि स्थापित न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए अधिकारियों को असीमित और अनियंत्रित शक्तियों से लैस किया जा सके।

16. हालाँकि उन सभी परिस्थितियों को पूरी तरह से निर्धारित करना संभव नहीं प्रतीत होता है जिनके तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस तरह की कवायद के परिणाम गंभीर नागरिक परिणामों का कारण बन सकते हैं और इसलिए, प्रभावित पक्षों को कार्यवाही को फिर से खोलने

का निर्णय लेने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिस समय के बाद बंद मामलों की फिर से जांच करने की मांग की जाती है, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए; अवधि जितनी लंबी होगी, आधार उतना ही मजबूत होना चाहिए।

17. अब सवाल यह है कि क्या प्राधिकरण उन सामग्रियों पर फिर से विचार करने पर कार्यवाही को फिर से खोलने का निर्णय ले सकता है जिन पर पहले विचार किया गया था। मेरे विचार में, ऐसा करने की अनुमति नहीं है और इस खंड की यह व्याख्या ऊपर उल्लिखित सदियों पुराने सिद्धांतों के अनुरूप होगी और उचित, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष खेल के अनुरूप होगी। यह न केवल भूमि-धारक को बल्कि राज्य को भी अनिश्चितता और परिणामी उत्पीड़न के निरंतर खतरे से बचाएगा; क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जिसे भूमि-धारक भी अपने पक्ष में प्रयोग करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और न केवल एक बार बल्कि बार-बार। यदि खंड को इसके व्यापक आयाम में अनियंत्रित और असीमित शक्ति का अर्थ लगाया जाता है, तो समाहर्ता जब एक पीड़ित भूमि-धारक द्वारा इसका उपयोग करने के लिए कहा जाता है, तो वह अपना दिमाग लगाए बिना प्रार्थना करने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि यह सत्ता का त्याग करने के बराबर होगा। इसलिए, मेरा मानना है कि यदि किसी मामले के अभिलेखों पर सामग्री को संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार में लिया जाता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है जो अंतिम हो जाता है (अपील और पुनरीक्षण पर या उसके अभाव में), तो इसकी अंतिमता का सम्मान किया जाना चाहिए और कार्यवाही को दूसरा विचार देने के लिए फिर से नहीं खोला जा सकता है। तथापि, यदि किसी ऐसी सामग्री या विषय को विचार से हटा दिया गया है जो इतना पर्याप्त हो कि किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचा सके, तो धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि यमुना राय बनाम बिहार राज्य मनु/बी. एच./0058/1984 (ऊपर) मामले के फैसले के पैराग्राफ 7 में श्री जस्टिस, बी. पी. झा की टिप्पणियां इस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, मेरा मानना है कि मामले का सही निर्णय लिया गया था।

18. मैं सुनवाई के दौरान मेरे सामने रखे गए अन्य मामलों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता हूँ। यदि इस न्यायालय के किसी खंड पीठ या एकल न्यायाधीश द्वारा इसके विपरीत कभी निर्णय लिया गया या कोई भी विपरीत टिप्पणी है तो इसे खारिज कर दिया गया माना जा सकता है।

19. अब मामले को गुण-दोष पर निर्णय के लिए उपयुक्त पीठ के पास वापस जाने दें, जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया है।

खण्डन (डिस्कलेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।